आईओसी की वजह से एशिया कप हॉकी के लिए भारत आ रही पाकिस्तान टीम

मुंबई। बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को भाग लेने की अनुमति देने के मुद्दे पर भारत सरकार मुश्किल में है। कई मौजूदा और पूर्व खेल प्रशासकों ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने और पाकिस्तान की टीम को भारत आने के लिए वीजा देने से इनकार करने का आग्रह किया है।

किसी भी देश को राजनीतिक कारणों से किसी टूर्नामेंट का हिस्सा न बनाना ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तान को एशिया कप हॉकी के लिए आने देना चाहती है।

दरअसल, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी चाहता है। अगर पाकिस्तान को अभी एशिया कप में भाग लेने से मना किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सामने नकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं, अगर पाकिस्तान भारत आता है, तो 2036 ओलंपिक की दावेदारी करते समय भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को मुश्किल नहीं आएगी।

पाकिस्तान टीम को एशिया कप हॉकी के लिए भारत आने देने का विरोध करने वाले शायद यह भूल रहे हैं कि आईओसी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत को मेजबानी का अधिकार न देने पर विचार करने को कहा था, क्योंकि कोसोवो के मुक्केबाजों और पाकिस्तानी निशानेबाजों को भारत में होने वाले आयोजनों में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने विशिष्ट स्पर्धा (पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल) की

ओलंपिक योग्यता स्थिति को रद्द कर दिया और अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत में वैश्विक स्पर्धाओं की मेजबानी पर विचार न करने को कहा।

राजगीर में होने वाले आगामी एशिया कप के लिए पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को वीजा देने से इनकार करने पर भारत द्वारा राजनीतिक कारणों से भागीदारी से इनकार करना, ओलंपिक समिति की नजर में एक अन्य बड़ा अपराध होगा।

ओलंपिक चार्टर में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के अनुरूप, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना खेल के अभ्यास तक पहुंच होनी चाहिए। राजनीतिक आधार पर वीजा देने से इनकार करना ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है।

इस प्रकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एशिया कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से भविष्य में मेजबानी के अधिकार को खतरा हो सकता है और खेलों में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। चार्टर राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, चाहे देशों के बीच राजनीतिक संबंध कुछ भी हों। यह राजनीतिक हस्तक्षेप से खेल महासंघों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर भी जोर देता है। राजनीतिक आधार पर वीजा देने से इनकार करना इस सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए, एशिया कप पर सरकार के कदम का समर्थन करने वाले लोग इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का भी हवाला दे रहे हैं, विशेष रूप से दो घटनाओं का जिनके कारण कुछ वर्ष पहले भारत को आईओसी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। भारत ने कोसोवो के एथलीटों को विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2018 में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया, जो एक नवगठित राष्ट्र है और देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। भारत ने 2019 में आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल विश्व कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के दो एथलीटों और एक अधिकारी को भी वीजा देने से इनकार कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप, आईओसी ने 21 फरवरी 2019 के अपने पत्र के माध्यम से आईओए को सूचित किया कि आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने भारत में भविष्य के आयोजनों और ओलंपिक से संबंधित आयोजनों की मेजबानी के लिए संभावित आवेदनों के संबंध में भारतीय एनओसी और सरकार के साथ सभी चर्चाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है, जब तक कि ओलंपिक चार्टर के नियमों के पूर्ण अनुपालन में सभी प्रतिभागियों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से स्पष्ट लिखित गारंटी प्राप्त नहीं हो जाती।

इसके अलावा, इसने यह भी सिफारिश की कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ गारंटी मिलने तक भारत में न तो खेल पुरस्कार दें और न ही खेल आयोजन करें। सिफारिश हटाने से पहले भारतीय सरकार को आईओसी को लिखित आश्वासन देना था। अन्य देशों को भी इस मुद्दे पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जैसे मलेशिया को इजरायली एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के कारण 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार खोना पड़ा और आईपीसी ने इस आयोजन को लंदन में स्थानांतरित कर दिया।

मैथ्यू शॉर्ट ने खेली कप्तानी पारी यूनिकॉर्न्स की एक रन से रोमांचक जीत

नई दिल्ली। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के 25वें मैच में रोमांचक जीत दर्ज की। टीम ने फ्लोरिडा में टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबला महज एक रन से जीता।

यह सीजन में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की सातवीं जीत रही, जबकि टेक्सास सुपर किंग्स को तीन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकीं इन दोनों टीमों ने अब तक नौ-नौ मैच खेले हैं। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने छह विकेट खोकर महज 148 रन बनाए।

टीम ने महज 19 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां से सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला।

मैथ्यू शॉर्ट ने हसन खान के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। हसन खान 25 गेंदों में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ने पारी को आगे बढ़ाया और 63 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से 80 रन जड़े। विपक्षी टीम की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि अकील हुसैन, नांद्रे बर्गर और नूर

अहमद को एक-एक सफलता हाथ लगी। इसके जवाब में टेक्सास सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट गंवाकर 147 रन बना सकी। टीम के लिए डेवोन फेरीरा ने 20 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जबकि सैतेजा मुक्कामल्ला ने 29 गेंदों में 34 रन जड़े। इनके अलावा शुभम रांजणे ने 28 रन की पारी खेली। टीम को जीत के लिए अंतिम ओवरों में 13 रन की दरकार थी, उसके पास चार विकेट शेष थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने चौका लगाया, लेकिन अगली बॉल पर कोई रन नहीं बना। तीसरी और चौथी गेंद पर एक-एक रन आए, जबकि पांचवीं गेंद पर मोहसिन ने फिर से चौका जड़ दिया। ऐसे में टीम को अंतिम गेंद पर जीत के लिए तीन रन की दरकार थी, लेकिन एक रन दौड़ते ही मोहसिन रन आउट हो गए। इसी के साथ सैन फ्रांसिस्को ने मुकाबला एक रन से जीत लिया।

सच बाजार

भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाना और गति एक साथ चल सकते हैं : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

रियो डी जेनेरियो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारत एक अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर प्रभाव पैदा करने वाले देश के रूप में अपनी दोहरी भूमिका के साथ न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आकांक्षाओं को साझा करने वाले सभी लोगों के लिए परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए मजबूत स्थिति में है। आधिकारिक यात्रा के दौरान चैलेंजेस फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल साउथ विषय पर फ्लेगशिप गवर्नेंस सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वित्तपोषित करना केवल धन जुटाने के बारे में नहीं है, यह निष्पक्षता, विश्वास और नेतृत्व का निर्माण करने से भी जुड़ा है।

उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, भारत के लिए, लाखों लोगों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका तक पहुंच

सुनिश्चित करने के लिए विकास में तेजी लाना आवश्यक है। साथ ही, हीटवेव, वॉटर स्ट्रेस और एक्ट्रीम वेदर की घटनाओं जैसे जलवायु संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं।

भारत नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और प्रांत-स्तरीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा, वास्तविक चुनौती डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच चयन करना नहीं है, बल्कि खास तौर पर उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीई) के साथ साझेदारी में ऐसी नीतियां तैयार करना है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करें। वित्त मंत्री ने आगे कहा, जैसा कि हम 2030 के एजेंडे की ओर प्रयास कर रहे हैं, कोरोना महामारी के बाद विकासशील देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) के लिए वित्तपोषण का अंतर सालाना 4.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। उन्होंने कहा, भारत एक अनोखे चौराहे पर खड़ा है। एक अरब लोगों की आकांक्षाएं तेजी से बदलते ग्रह की अनिवार्यताओं के साथ मिलती हैं। भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाना और गति एक साथ चल सकते हैं। यूपीआई, आधार और जन धन जैसी परिवर्तनकारी नीतिगत पहलों के माध्यम से, देश ने वित्तीय समावेशन को अंतिम मील तक पहुंचाया है।

वित्त मंत्री ने कहा, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए 220 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की स्थापना जैसे कार्यक्रमों से हमारी नीति इकोसिस्टम को मजबूती मिली है।

हाल के वर्षों में, भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी डिस्क्लोजर मेनडेट और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए प्रपोज्ड टैक्सोनॉमी जैसी पहलों के माध्यम से ग्रीन फाइनेंस के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

भारत 153 देशों को निर्यात करता है खिलौने, सरकार एक और प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी में : पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग, जो कभी आयात पर बहुत अधिक निर्भर था, अब घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और 153 देशों को निर्यात कर रहा है। 16वें टॉप बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि यह बदलाव लगातार नीतिगत समर्थन, गुणवत्ता मानकों के प्रवर्तन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मजबूत करने के माध्यम से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन ने भारत को गुणवत्ता के प्रति जागरूक देश बनाने में मदद की है और घरेलू खिलौना निर्माताओं को वैश्विक मानदंडों को पूरा करने में सक्षम बनाया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत की 1.4 बिलियन की आबादी एक विशाल कैप्टिव बाजार प्रदान करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एक स्वाभाविक लाभ पैदा करती है। इस पैमाने के साथ, उद्योग

लागत दक्षता प्राप्त कर सकता है और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

उन्होंने कहा कि बड़ा घरेलू बाजार न केवल विस्तार का समर्थन करता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए आधार का काम भी करता है।

उन्होंने बताया कि सरकार खिलौना क्षेत्र के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय खिलौना निर्माताओं की डिजाइन क्षमताओं को बढ़ाकर, गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सुनिश्चित कर, पैकेजिंग मजबूत कर और ब्रांड निर्माण को समर्थन देकर उन्हें विश्व स्तरीय बनने में मदद करना है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने वैश्विक बाजार में आगे आने के लिए उद्योग को अच्छी ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और मजबूत उत्पाद डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अगर इन तीन पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है तो भारतीय खिलौने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत अपील हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने %वोकल फॉर लोकल% पहल की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने इसे संदेह के साथ देखा था, क्योंकि विदेशी उत्पाद उपभोक्ता की पसंद पर हावी थे।

सस्ते में सोना खरीदने का मौका, चांदी का दाम भी गिरा

नई दिल्ली। सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है। दोनों कीमती धातुओं की कीमत में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 316 रुपए कम होकर 97,021 रुपए हो गया है, जो कि पहले 97,337 रुपए था। 22 कैरेट के सोने का दाम कम होकर 88,871 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 89,161 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट के सोने की कीमत 73,003 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 72,766 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का दाम 40 रुपए कम होकर 1,07,580 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,07,620 रुपए प्रति किलो था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 अगस्त 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.13 प्रतिशत बढ़कर 96,908 रुपए और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.16 प्रतिशत बढ़कर 1,08,404 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी दोनों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। खबर लिखे जाने तक कॉमैक्स पर सोना करीब 0.03 प्रतिशत बढ़कर 3,343.85 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.13 प्रतिशत बढ़कर 37.13 डॉलर प्रति औंस पर थी। बाजार के जानकारों के मुताबिक, सोना पिछले एक हफ्ते से एक सीमित दायरे में बना हुआ है। अमेरिकी ट्रंप की ओर से टैरिफ को लेकर दी गई 9 जुलाई की डेडलाइन नजदीक आ रही है। इस पर नए अपडेट के बाद ही सोने-चांदी की दिशा तय होगी। 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 20,859 रुपए या 27.38 प्रतिशत बढ़कर 97,021 रुपए पर पहुंच गया है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल 36,000 रिटेल आउटलेट्स पर सौर ऊर्जा का कर रहा उपयोग : हरदीप पुरी

नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और इसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने 36,000 से अधिक खुदरा आउटलेट्स को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करके भारत की इस ताकत का विस्तार किया है, जहां अधिकांश परिचालन सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह सराहनीय प्रयास न केवल बिजली बिलों को कम करता है बल्कि %हरित भारत% के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है।

उन्होंने कहा, नया भारत अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पूरक पहलुओं के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। चाहे घर की छत हो, दफ्तर हो या फैक्ट्री... अगर थोड़ी सी भी जगह है, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। यह ऊर्जा की

जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा साधन साबित हो रहा है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में भारी उछाल आया है जो 2014 में मात्र 2.82 गीगावाट से बढ़कर इस साल 31 मार्च तक 105.65 गीगावाट हो गई है।

कुल स्थापित सौर क्षमता में से ग्राउंड-माउंटेड इंस्टॉलेशन क्षमता 81.01 गीगावाट, रूफटॉप सोलर क्षमता 17.02 गीगावाट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट के सौर घटकों की क्षमता 2.87 गीगावाट और ऑफ-ग्रिड सिस्टम क्षमता 4.74 गीगावाट है।

यह वृद्धि विभिन्न श्रेणियों में सौर ऊर्जा के निरंतर उपयोग को दर्शाती है।

सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में विस्तार को सौर सेल और वेफर्स के मजबूत घरेलू उत्पादन का समर्थन प्राप्त है, जो 2014 में लगभग न के बराबर था। भारत ने अब 25 गीगावाट सौर सेल उत्पादन और 2 गीगावाट वेफर उत्पादन के साथ एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है।

इसके अलावा पुरी ने कहा कि दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में 3.6 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.5 करोड़ हो गई है, जिसमें 95 प्रतिशत 30 दिनों के भीतर प्रोसेस किए गए हैं।

ये आंकड़े भारत की उभरती वित्तीय संस्कृति को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि जब कराधान का प्रबंधन ईमानदारी से किया जाता है, तो यह सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। इसे मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में देखा जा सकता है।

भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है और संरचनात्मक कारकों के कारण यही मांह वित्त वर्ष 2026-29 में 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगी। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

बीएनपी परिबास इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमतों में तेजी से सुधार हुआ है और मानसून के जल्दी आने के बावजूद कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन मौजूदा स्तरों पर कीमतों की स्थिरता वित्त वर्ष 2026 की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्लेषक निरांश जैन ने कहा, हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री प्लेयर्स द्वारा लाभप्रदता को प्राथमिकता दिए जाने और उद्योग के निरंतर कंसोलिडेशन के कारण प्राइसिंग पावर में सुधार होगा।

भारत का सीमेंट क्षेत्र उत्पादन के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। हालांकि हाल के वर्ष नई सप्लाई, कम उपयोग और सीमित मूल्य निर्धारण शक्ति के मामले में चुनौतीपूर्ण रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हमें लगता है कि साइकल अब बदल रहा है और बेहतर दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। उद्योग को ओवरसप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन हम उद्योग के कंसोलिडेटेड होने के साथ मांग/आपूर्ति की गतिशीलता में सुधार देख रहे हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में मई में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले महीने सीमेंट, स्टील, कोयला और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर क्रमश: 3.4, 4.5 और 1.0 प्रतिशत देखी गई। आईसीआरए की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सीमेंट सेक्टर की वॉल्यूम मई में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 39.6 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। वित्त वर्ष 26 के पहले दो महीनों में सीमेंट सेक्टर में सकारात्मक रुझान जारी रहा, जिससे वॉल्यूम 8 प्रतिशत बढ़कर 78.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है।